nwda.gov.in

जल संरक्षण में मप्र अव्वल, ओडिशा दूसरे नंबर पर

मनीष तिवारी ● नई दिल्ली

मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण, प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जनजागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून को दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को इन पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। मंत्रालय ने विजेताओं की सूची सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। ओडिशा दूसरे और आंध्र प्रदेश तथा बिहार तीसरे स्थान पर रहे हैं।

सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम को मिला है। तमिलनाडु का नमक्कल दूसरे और तेलंगाना का आदिलाबाद तीसरे स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत (भद्राद्री कोटागुडम जिला) को पहला स्थान मिला है, जबकि तमिलनाडु के करूर जिले की कदावुर ग्राम पंचायत तथा केरल के तिरुअनंतपुरम जिले की मणिकल ग्राम पंचायत को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के जालना जिले की कडेगांव तथा मेघालय के री भोई जिले की मकीरडेप ग्राम पंचायत है।

सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में चंडीगढ़ नगर निगम ने बाजी मारी है। दूसरे स्थान पर इंदौर नगर निगम रहा, जबकि तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सूरत नगर निगम तथा महाराष्ट्र की मलकापुर नगर परिषद (सतारा) है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि यह समारोह सभी विजेताओं, प्रतिभागियों और विभिन्न संगठनों को एक मजबूत साझेदारी के साथ आगे बढ़ने और जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किए गए थे।

उत्तर प्रदेश के निकायों को अनियोजित विकास थामना होगा

मनीष तिवारी ● नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि 29 मई से अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं और उनके सामने चुनौतियों की एक लंबी सूची मौजूद है। लेकिन विशेषज्ञों ने यह उम्मीद जताई है कि यदि पिछले पांच साल में बनी जमीन पर सही तरह से काम किया जाए तो देश के सबसे बड़े राज्य के शहर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच साल में लगभग सभी निकायों के लिए अगले पच्चीस साल तक का मास्टर प्लान तैयार किया है।

पशिम तिवारी ●

उत्तर प्रदेश के निकायों, खासकर नगर निगमों में प्लानिंग पर परामर्श देने वाले आल, इंडिया इंस्टीट्यूट आफ लोकल गवर्नमेंट के तकनीकी निदेशक पशिम तिवारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जिसने अपने सभी निकायों की जीआइएस मैपिंग की है। यह भावी शहरी विकास की पहली जरूरत है। अब यह नए चुने गए जनप्रतिनिधियों पर है कि वे प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर अपने एजेंडे को पूरा करें। उत्तर प्रदेश ने 15वें वित्त आयोग से शहरी विकास के लिए पांच साल के लिए 2.80 लाख करोड़ रुपये मांगे थे। यह बड़ी राशि है, लेकिन राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए शहरों को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा।